वैश्विक जलवायु राजनीति में भारत की भूमिका

डॉ. नेहा पूनिया

परिचय

जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, जो न केवल पर्यावरणीय बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। वैश्विक जलवायु राजनीति में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक होने के साथ-साथ एक विकासशील देश है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अत्यधिक प्रभावित है। भारत की जलवायु नीतियों और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसकी सक्रियता ने इसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

भारत की जलवायु स्थिति और चुनौतियाँ

1. भौगोलिक और सामाजिक संदर्भ

- भारत की भौगोलिक स्थिति इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, और हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं।
- देश की 1.4 अरब की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, जो मानसून और जलवायु पर अत्यधिक निर्भर है।

2. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में यह विकसित देशों से काफी पीछे है।
- ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग, और कृषि क्षेत्र प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र हैं।

3. विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण

- भारत को अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकासशील जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है।
- गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा सुरक्षा, और औद्योगिक विकास जैसे लक्ष्यों के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।

वैश्विक जलवायु राजनीति में भारत की भूमिका

औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन-गहन गतिविधियों का एक अनुचित परिणाम जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी और सबसे बेजोड़ चुनौती है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मानवीय गतिविधियों ने पूर्व-औद्योगिक युग से ग्रह को लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया है। भारत में, जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक चुनौती के रूप में उभरा है। बदलते मौसम पैटर्न, अप्रत्याशित वर्षा आदि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दर्शाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) शुरू की, जिसमें आठ राष्ट्रीय मिशन हैं। NAPCC के तहत राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE) में जलवायु परिवर्तन शमन विशेषताओं वाले कार्यक्रम शामिल हैं। NMEEE के तहत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना ने लगभग 30 मिलियन टन CO2 से बचने में मदद की है और यह परिकल्पना की गई कि 2020 तक, 30 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचा जा सकता है। अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) में भाग ले रहा है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय संचार और उत्सर्जन सूची की समीक्षा करना है।

भारत ने वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लगातार कार्रवाई की वकालत की है, जिसमें मानव कल्याण और पर्यावरण के बीच अंतर्संबंध पर जोर दिया गया है। 2023 में, जब भारत ने जी-20 की अध्यक्षता संभाली, तो अध्यक्षता के दौरान इसका विषय 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' था। यह विषय भारत के इस दृष्टिकोण पर जोर देता है कि दुनिया भर में मानव जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए, हमारे समाज में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सामूहिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। जी-20 शिखर सम्मेलन में, भारत ने जलवायु परिवर्तन से सामूहिक रूप से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत का मानना है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों में सार्वभौमिक भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है।[1]

1. पेरिस समझौता और भारत:

2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत अग्रणी था। नवंबर-दिसंबर 2015 के दौरान पेरिस में आयोजित सीओपी के 21वें सत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्थायी कार्बन भविष्य के लिए आवश्यक कार्यों और निवेशों को तेज करने और तीव्र करने के लिए ''पेरिस समझौता'' नामक एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखकर जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना था। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की पुष्टि की, जिसके तहत सदस्य देशों को पूर्व-औद्योगिक वर्षों की तुलना में वैश्विक औसत तापमान को $2^{\circ}C$ से नीचे रखने के लिए CO_2 उत्सर्जन को रोकने के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ बनाने की आवश्यकता थी।[2]

2. यूएनएफसीसीसी को एनडीसी:

पेरिस समझौते के पश्चात, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को यूएनएफसीसीसी को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किए, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर देश की प्रतिबद्धता का समर्थन किया गया। भारत ने अपनी 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)' के तहत 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 40% तक ले जाने और उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33-35% तक कम करने का वादा किया, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह विकासशील देशों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

UNFCCC को प्रस्तुत भारत के NDCका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है[3]:

- संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों पर आधारित एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली को आगे बढ़ाना और उसका प्रचार करना।
- आर्थिक विकास के इसी स्तर पर अन्य देशों द्वारा अब तक अपनाए गए मार्ग की तुलना में जलवायु के अनुकूल और स्वच्छ मार्ग को अपनाना।
- 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड

(जीसीएफ) सहित कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सहायता से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।

- 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में विकास कार्यक्रम में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के लिए बेहतर अनुकूलन करना।
- आवश्यक संसाधन और संसाधन अंतराल को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त शमन और अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिए विकसित देशों से घरेलू और नए और अतिरिक्त फंड जुटाना।
- भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी के त्वरित प्रसार और ऐसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त सहयोगी अनुसंधान और विकास के लिए क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला बनाना।

3. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नेतृत्वः

(क) सीओपी-28 शिखर सम्मेलन 2023-

सीओपी-28 शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत उन कुछ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है। हम 11 साल पहले ही उत्सर्जन तीव्रता से संबंधित गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। हमने गैर-जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य तय समय से नौ साल पहले ही हासिल कर लिया है। और, भारत यहीं नहीं रुका। हमारा लक्ष्य 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना है। हमने गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसने उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए भारत के समर्पण को प्रदर्शित किया।'[4] यह उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य की ओर बढ़ने के भारत के समर्पण को प्रदर्शित करता है।[5]

(ख) अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)-

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास

किया है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाई है। भारत ने ''अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)'' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।[6]

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की परिकल्पना भारत ने सौर-समृद्ध देशों के एक सहकारी नेटवर्क के रूप में की थी। 2015 में, पेरिस जलवायु सम्मेलन में, भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा की मदद से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के गठबंधन के रूप में आईएसए की घोषणा की।[7] आईएसए का गठन टोरिड जोन के देशों के बीच सहयोग के रूप में किया गया था, जिसमें कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र शामिल हैं, जहां सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में है और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक है।[8] गठबंधन में शुरुआत में ज्यादातर भागीदार उष्णकटिबंधीय देश थे। हालाँकि, अक्टूबर 2018 में इसकी पहली आम सभा के दौरान, आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते में एक संशोधन किया गया, जिससे कोई भी इसका सदस्य बन सकता था और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए भागीदारी को खोल दिया गया। वर्तमान में, आईएसए के मुख्य कानूनी पाठ्स पर 116 देश हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिनमें से 94 पूर्ण सदस्य बन गए हैं।[9]

आईएसए का संचालन इसके व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित नौ समर्पित कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। इन कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर किफायती वित्त, कृषि उपयोग के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाना (एसएसएएयू), सोलराइजिंग हीटिंग एवं कूलिंग सिस्टम, स्केलिंग सोलर मिनी-ग्रिड, स्केलिंग सोलर रूफटॉप्स, स्केलिंग सोलर ई-मोबिलिटी एंड स्टोरेज, सोलर पार्क, सोलर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर बैटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट शामिल हैं।[10] विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर अपने समावेशी दृष्टिकोण एवं रणनीतिक फोकस के माध्यम से, आईएसए जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण से निपटने के वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने सदस्य देशों की सौर क्षमता का लाभ उठाकर और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, आईएसए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने एवं वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।[11]

(ग) वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी)-

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के विचार का समर्थन करने हेतु, पीएम मोदी ने 2018 में आईएसए असेंबली में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी) पहल का प्रस्ताव रखा।[12] 2021 में सीओपी-26 वर्ल्ड लीडर्स समिट के दौरान इसके लॉन्च के साथ इसे और गति मिली।[13] 80 से अधिक देशों द्वारा समर्थित, ओएसओडब्ल्यूओजी पहल के जरिए विश्व स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति के नेटवर्क को जोड़ने एवं राष्ट्रीय सीमाओं से परे परस्पर जुड़े बिजली ग्रिड के विकास में सहायता करने का आह्वान किया गया।[14] मिनी-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड समाधानों की मदद से ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ाकर और आसान बनाकर, यह पहल एक स्वच्छ-संचालित भविष्य में बदलाव की उम्मीद जगाती है।[15]

इस पहल का उद्देश्य जुड़ाव के तीन प्रमुख स्तंभों- राजनीतिक जुड़ाव, संस्थागत जुड़ाव और अनुसंधान व ज्ञान साझा करने के आधार पर वैश्विक सहयोग और इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

(घ) लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT)-

स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली एक और पहल उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह (लीडआईटी) है। लीडआईटी को 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था और इसे जलवायु-सुरक्षित औद्योगिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र के रूप में देखा गया था।[16] यह प्रयास स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा विश्व आर्थिक मंच (WEF) के समर्थन से शुरू किया गया था और यह भारी उद्योग से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को लक्षित करने वाली पहली वैश्विक उच्च-स्तरीय पहल का प्रतिनिधित्व करता है।[17]

स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार, उद्योग वैश्विक CO2 उत्सर्जन में लगभग 30% का योगदान करते हैं। इसलिए, वैश्विक तापमान को दो डिग्री तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में उत्सर्जन में कमी की अधिक आवश्यकता है।

- भारत ने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर जोर दिया है।

3. साझेदारी और कूटनीति:

- भारत ने यूरोपीय संघ, अमेरिका, और चीन जैसे प्रमुख देशों के साथ जलवायु

सहयोग पर समझौते किए हैं।

- G-20 और BRICS जैसे मंचों पर भारत ने जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्रवाई की वकालत की है।

अन्य प्रयास-

एनएमईईई कार्यक्रम के अलावा, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे उपकरणों के लिए मानक और लेबलिंग, इमारतों के लिए ईसीबीसी, टिकाऊ परिवहन, मांग पक्ष प्रबंधन और एसएमई में ऊर्जा दक्षता आदि। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, 2005 और 2014 के बीच 21% की उत्सर्जन तीव्रता में कमी देश द्वारा पहले ही हासिल की जा चुकी है। यह परिदृश्य दर्शाता है कि भारत सरकार की पहल एनडीसी में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

भारत की जलवायु नीतियाँ-

1. राष्ट्रीय कार्य योजना:

भारत ने 2008 में 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)' शुरू की, जिसमें 8 प्रमुख मिशन शामिल हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, और जल मिशन।[18]

2. नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति:

भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें से सौर और पवन ऊर्जा का बड़ा हिस्सा है।

3. हरित हाइड्रोजन मिशन:

भारत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई पहलों के जरिए शमन योजनाओं में अग्रणी भूमिका कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और विभिन्न निजी पक्ष इस मुद्दों के समाधान हेतु सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जलवायु स्थिरता के प्रति एक ऐसा ही समकालीन दृष्टिकोण है, जिसने बहुत सराहना बटोरी है। भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ लागू की हैं, जिससे औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का

वार्षिक ऊर्जा आयात 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसने इस चुनौती को दूर करने तथा देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, निर्यात एवं विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की स्थापना को प्रेरित किया है। इस पहल के माध्यम से नीति समर्थन जारी है, जिसके माध्यम से 2030 तक सालाना पांच मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 197 बिलियन रुपये आवंटित किया जाएगा। हालांकि, निर्यात के अवसर काफी अधिक हैं, हरित हाइड्रोजन के लिए स्थानीय मांग पैदा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

4. वन और जैव विविधता संरक्षण:

'राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम' और 'जैव विविधता अधिनियम' जैसे प्रयास भारत की जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों का हिस्सा हैं।

भारत की जलवायु राजनीति का सामाजिक प्रभाव:

1. सामाजिक आंदोलन और जागरूकता:

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में भारत में जागरूकता बढ़ी है। कई सामाजिक आंदोलनों और संगठनों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, जैसे कि पर्यावरणीय न्याय, जलवायु शरणार्थियों की स्थिति, और जलवायु संकट से निपटने के लिए नीति सुधार।

2. आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश किया है, जैसे कि जलवायु पूर्वानुमान, मौसम विज्ञान, और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में।

जलवायु राजनीति से जुड़ी भारत की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ-

1. वित्तीय और तकनीकी बाधाएँ:

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकी की कमी एक बड़ी चुनौती है।

2. नीतियों का कार्यान्वयन:

भारत में कई जलवायु नीतियाँ बनाई गई हैं, लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन अक्सर धीमा और असंगत रहा है।

3. **अंतरराष्ट्रीय दबाव:**

विकसित देश भारत पर अधिक उत्सर्जन कटौती का दबाव डालते हैं, जबकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से कम उत्सर्जन किया है।

भविष्य की रणनीतियाँ और सुझाव

1. **स्थायी विकास पर ध्यान:**

भारत को अपनी विकास नीतियों को जलवायु परिवर्तन के साथ संतुलित करना होगा।

2. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:**

जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी।

3. **स्थानीय और सामुदायिक भागीदारी:**

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

4. **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश:**

भारत को सौर, पवन, और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष

विश्व को जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और दुनिया भर में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से बढ़ रहे हैं। जलवायु-संबंधी आपदाओं की बढ़ती संख्या और उन विनाशकारी परिणामों को कम करना महत्वपूर्ण है जिनका दुनिया पहले से ही सामना कर रही है। संसाधनों की कमी, वायु प्रदूषण, बढ़ते वैश्विक तापमान एवं ग्लेशियर के पिघलने के व्यापक प्रभावों से कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट होती है। यदि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग मौजूदा स्तर से जारी रहे तो गंभीर परिणाम होंगे।

भारत ने वैश्विक जलवायु राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत किया है और इसे एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इसे अपनी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए स्थायी विकास के मार्ग पर चलना होगा।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

1. *मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,* गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
2. *पेरिस अग्रीमेंट डॉक्यूमेंटेशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज* (यूएनएफसीसीसी)
3. वही
4. नरेन्द्र मोदी, *प्रधान मंत्री द्वारा एचओएस/एचओजी के सीओपी-28 के उच्च स्तरीय खंड के उद्घाटन पर विशेष संबोधन,* प्रेस सूचना ब्यूरो, 1 दिसंबर 2023
5. नरेन्द्र मोदी, (2023, 1 दिसंबर), *प्रधान मंत्री द्वारा एचओएस/एचओजी के सीओपी-28 के उच्च स्तरीय खंड के उद्घाटन पर विशेष संबोधन,* प्रेस सूचना ब्यूरो
6. *इंटरनेशनल सोलर अलायन्स* (आईएसए) रिपोर्ट्स.
7. वी. झा, *इंटरनेशनल सोलर अलायन्स, ब्रिजिंग द गेप,* सी.एस.ई.पी, 18 अक्टूबर, 2023
8. वही
9. वही
10. गुव्वाडी, *इंटरनेशनल सोलर अलायन्स, ब्रिजिंग द गेप,* सी.एस.ई.पी., 2023
11. वही
12. *अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन,* 19 मार्च, 2024
13. वही
14. वही
15. वही
16. लीड इट. (एन.डी.), *आवर मिशन, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन,* 18 मार्च, 2024

17. लीड इट. (एन.डी.), *आवर मिशन, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन,* 18 मार्च, 2024

18. *नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज* (एनएपीसीसी)

अतिथि व्याख्याता
राजनीति विज्ञान
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अलसीसर (झुंझुनू)